

जो ट्रीटमेंट उसके साथ अब किया जा रहा है अगर यही ट्रीटमेंट चलता रहा तो वह वक्त भी आएगा जब किसान अपनी चीज को नहीं बेचेगा। आप सोचते हैं कि सस्ती मिले। क्या आप किसान को कहीं का छोड़ना चाहते हैं? अगर यही बात है तो देखना क्या हालत होती है और कहां से आपको खाने को मिलता है।

महंगाई को तो आप रोकें लेकिन जो इगनोर्ड डोमेन है, जो इगनोर्ड स्फीयर है, जो देहात है, उनको आपको उठाना पड़ेगा और वहां उनको आपको इंस्टिट्यूट देने होंगे, उनके साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करना होगा, उनको अच्छा भाव देना होगा और उनको एनकरेजमेंट देना होगा। जब आपने ऐसा किया तभी महंगाई कम होगी।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : आज की जो चर्चा है, इस में कोई शक नहीं है कि उस में सब से बड़ा राक्षस जो है, वह महंगाई है। उसके लिए किसी को अगर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो इसी सरकार को ठहराया जा सकता है। यह इसलिए भी है कि यह सरकार उत्तराधिकार की सरकार है। यह नहीं कहा जा सकता है कि अभी हम को आए हुए थोड़े दिन हुए हैं, हम काबू नहीं कर पा रहे हैं।

समापति महोदय : अगली बार जब यह विषय आएगा तब आप बोलियेगा।

17.29 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION *Re:*  
RESUMPTION OF TRADE BETWEEN  
INDIA AND PAKISTAN

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : यह प्रश्न भारत-पाकिस्तान व्यापार के सम्बन्ध में है। इस प्रश्न को उठाने की आवश्यकता इसलिए पैदा हुई कि पाकिस्तान के मंत्री श्री रहमान

साहब ने हाल ही में एक वक्तव्य दिया था कि भारत और पाकिस्तान में तो व्यापार के मामले में अवरोध पैदा हो गया है, उसको दूर किया जाना चाहिये और भारत पाकिस्तान व्यापार में फिर उसी तरह से सामंजस्य और सहयोग स्थापित किया जाना चाहिये।

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH): May I just clarify that there is no minister of this name? I think, what has appeared in the question is not clear; my intervention is only for giving information. He happens to be the Chairman of their Chamber of Commerce and Industry.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): The matter ends.

SHRI SWARAN SINGH: That is what I say.

श्री भोगेन्द्र झा : यही बात खत्म नहीं होती, यहीं से बात शुरू होती है। इसका आधार यह है कि रहमान साहब ने जो वक्तव्य दिया है और पूर्वी पाकिस्तान का लोकमत भी जिस तरह से जागृत हो रहा है और वह भी भारत के साथ व्यापार बढ़ाने को इच्छुक है, उसकी वजह से पाकिस्तान सरकार के रुख में भी नमी आई थी।

रहमान साहब के नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल वाणिज्य के सम्बन्ध में आया था उसने जो राय दी थी और यह कहा था कि फिर से व्यापार दोनों देशों में शुरू होना चाहिये, उसके बाद से भारत सरकार ने कोई पहल नहीं की है। भारत सरकार ने ऐसा कोई एलान नहीं किया है कि हम इस बात का स्वागत करते हैं। उसने इस बीच कोई नया कदम नहीं उठाया है जिससे पता चलता कि पाकिस्तान के अन्दर जो सहयोग इस क्षेत्र में चाहने वाले तत्व हैं, जो शक्तियां हैं, उनको बढ़ावा मिलता है। उलटे जवाब यह दिया गया है कि पाकिस्तान की ओर से कोई उत्साहजनक जवाब नहीं आया है। यह कह कर बात को समाप्त कर दिया गया है।

[श्री भोगेन्द्र झा]

इस पृष्ठभूमि में मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले साल हमारी प्रधान मंत्री अफगानिस्तान गई थीं। उनकी वापसी के बाद जो संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ था उसमें यह कहा गया था कि भूमि के रास्ते व्यापार अफगानिस्तान के साथ प्रारम्भ करने की सम्भावनायें हैं और उसके रास्ते में जो बाधा है, वह दूर होगी, यह आशा भी व्यक्त की गई थी। लेकिन यह आशा निराधार साबित हुई है। ईरान के साथ भी हमारी कुछ वार्ता चल रही थी और भूमि के रास्ते ईरान और भारत के बीच भी व्यापार चले, इसका रास्ता निकालने की भी उसमें बात थी। अब ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार होता है और भूमि के रास्ते होता है तो बीच में पाकिस्तान आता है। इस वास्ते अगर भारत, अफगानिस्तान और ईरान में व्यापार के क्षेत्र में सहयोग की बात होती है तो उसमें पाकिस्तान का सहयोग भी अपेक्षित हो जाता है। काबुल में जब वार्ता हुई थी तो उसके बाद यह झलक मिल गई थी कि पाकिस्तान इसके विरोध में नहीं है और वह भी सहमत हो गया है। लेकिन उसके बाद जो तत्व भारत का बटवारा कराने के लिए सक्रिय रहे हैं, भारत में भी जो विभेद पैदा करने वाले तत्व रहे हैं, वे सक्रिय हुए और हमारे देश में अमरीका परस्त अखबारों ने भी आवाज उठाई कि कोसीगिन की राय पर यह बात हुई है, सोवियत सरकार की राय पर यह बात हुई है। मेरी आशंका है एक जो मैं इस सदन के सामने जाहिर करना चाहता हूँ और वह यह है कि उनके दबाव में आ कर भारत सरकार ने, काबुल में जो संयुक्त विज्ञप्ति निकाली थी, उसके बाद जो सम्भावनाएँ पैदा हुई थीं कि इन देशों के बीच में व्यापार में वृद्धि हो सकती थी, अपने प्रयत्नों को शिथिल कर दिया और उन तत्वों के आगे भारत सरकार झुक गई। उसने आगे का प्रयास अमरीका के

दबाव में आकर छोड़ दिया। यह हमारी आशंका है और यह हमारा अभियोग भी है। जो जवाब मंत्री महोदय ने दिया है उस जवाब से भी यह अभियोग प्रमाणित होता है।

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहिये, इस सम्बन्ध में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। लेकिन जो तत्व इस मार्ग में बाधक हैं उनका क्या हित है, यह भी सदन के सामने कई बार आ चुका है। आप जूट की बात को लें। जूट उत्पादकों के हितों के विरुद्ध जाकर मिल मालिकों के हितों का सरकार संरक्षण करती रही है। इसका नतीजा यह निकला है कि जूट का उत्पादन उतना नहीं बढ़ सका जितना बढ़ना चाहिये। गत साल तो उसका उत्पादन घट भी गया था। आज हमारी हालत यह है कि जहाँ दूसरी योजना के अन्तर्गत हम जूट के मामले स्वावलम्बी बन गए थे वहाँ आज हमें बाहर के देशों से जूट मंगाना पड़ रहा है और उसके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है, डालर खर्च करके मंगानी पड़ रही है। जूट पाकिस्तान में और हमारे यहाँ होता है। लेकिन वही जूट अमरीका के जरिये यहाँ आता है। अगर भारत पाकिस्तान का सीधा वाणिज्य सम्बन्ध स्थापित हो जाए और उसी तरह से हो जाए जैसा वह 1965 के पहले था तो यह विदेशी मुद्रा हमारी बच सकती है। पिछले दिनों मछली की चर्चा हुई थी। पाकिस्तान से मछली आए बदले में यहाँ से कोयला जाए, यह भी कहा गया था। इस तरह से वहाँ से जूट मछली आदि आ सकती है और यहाँ से कोयला आदि भेजा जा सकता है।

सभापति महोदय, दोनों देशों का अर्थ तंत्र एक दूसरे पर आश्रित रहा है। भारत एक ही देश था। साम्राज्यवादियों के षड्यंत्र के कारण उसका बंटवारा हुआ। अमरीका का हित इसमें ही है कि वहाँ से हम जूट लें।

इस वास्ते आज भी वह इस व्यापार के मार्ग में बाधक बन रहा है और चाहता है कि भारत और पाकिस्तान में व्यापार फिर से चालू न हो ।

मैं जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जो प्रयास काबुल की विज्ञप्ति के साथ छोड़ दिया है, क्या उसको वह फिर प्रारम्भ करने जा रही है या नहीं करने जा रही है ? इन चार देशों के साथ भूमि के रास्ते से व्यापार करने के लिए पाकिस्तान का सहयोग अनिवार्य है । 1965 के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ पुनः व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक अच्छा कदम उठाया था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने नकारात्मक रुख अपनाया था । आज पाकिस्तान में हालात बदल रहे हैं । हमें आशा है कि चुनावों के बाद वे और भी बदलेंगे । खास तौर पर पूर्वी पाकिस्तान में जो लोकसत्ता है, उसका प्रभाव पश्चिमी पाकिस्तान पर भी पड़ेगा, यह हमारी उम्मीद है ।

क्या भारत सरकार यह ऐलान करेगी कि 1965 से पहले भारत-पाकिस्तान व्यापार की जो हालत थी, उसको फिर से कायम करने के लिए भारत सरकार केवल उद्यत ही नहीं है, बल्कि उसके लिए पहलकदमी भी करेगी और इस सम्बन्ध में बाबाबन्ता तौर पर पाकिस्तान सरकार को लिखेगी ? इस विषय में पाकिस्तान का रुख चाहे जो कुछ भी हो, अपने लोकमत के सामने उसको झुकना पड़ेगा । जैसा कि यहां पर कहा गया है, पाकिस्तान का चेम्बर आफ कामर्स भारत के साथ पुनः व्यापार सम्बन्ध चालू करना चाहता है । जिन तत्त्वों का वह प्रतिनिधित्व करता है, वे अपने देश में इसके लिए जोर डालेंगे । साम्राज्यवादी दबाव के कारण इसमें अवरोध आ गया है । हमारे देश में भी बड़े करोड़पतियों का एक तबका है, जो चाहता है कि इस मामले में पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध न सुधरें । दुर्भाग्य से हमारे देश के जूट मिलों के

मालिक, और उनसे प्रभावित अखबार भी, यह नहीं चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में पुनः व्यापार प्रारम्भ हो, क्योंकि इससे उनके लिए विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में घांवली करने, अमरीका और विलायत के साथ सांठगांठ करने और देश का अहित करके मिल-मालिकों का हित साधन करने का रास्ता बन्द हो जायेगा । (व्यवधान) वे लोग चाहते हैं कि अमरीका या इंग्लैंड से जूट आये, लेकिन वह सीधे पाकिस्तान से आये, यह उनको प्रिय नहीं है ।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार यह ऐलान करने के लिए तैयार है कि 1965 से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में व्यापार की जो स्थिति थी, उसको दृढ़ करने के लिए, या कम से कम उस स्थिति को फिर से लाने के लिए, वह पहल-कदमी करेगी और इसके लिए पाकिस्तान को निमंत्रण देगी ।

**श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) :** सभा-पति महोदय, माननीय सदस्य, श्री भोगेन्द्र झा, ने दो बातों की चर्चा की है : एक तो पूर्वी पाकिस्तान के लोकमत की और दूसरे, इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा पहल न किये जाने की । जहां तक पूर्वी पाकिस्तान के लोकमत का सवाल है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अगर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की चलती और अगर वे अपनी इच्छा के मुताबिक काम कर सकते, तो पूर्वी पाकिस्तान कभी का हमारे साथ मिल गया होता । लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान सरकार का आधिपत्य है, जिसको देखते हुए पूर्वी पाकिस्तान के लोकमत का कोई मूल्य नहीं है ।

जहां तक भारत सरकार द्वारा पहल किये जाने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिए हर मामले में पहल की है । मैं कोई भारत सरकार की

[श्री बेणी शंकर शर्मा]

वकालत करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ— उसकी तरफ से सरदार साहब बोलेंगे—, लेकिन जो तथ्य है, वह मैं बताना चाहता हूँ। आप नेहरू-लियाकत पैकट, नेहरू-नून पैकट और अयूब-शास्त्री पैकट, जिसको ताशकन्द समझौता कहा जाता है, इन सबका इतिहास देखिये। हमने इन समझौतों के बारे में अपने सब दायित्वों को निभाया है। ताशकन्द समझौते के बारे में भी हमारी तरफ से जो कुछ किया जाना था, वह हमने किया। हमने पाकिस्तान का जो माल सीज किया था, वह हमने एकतरफा तौर पर उसको वापिस कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने हमारी एक भी चीज वापिस नहीं की। इसके बावजूद भारत सरकार को यह दोष देना कि वह पहल नहीं करती है, यह सबसे बड़ा अन्याय है।

क्या मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि अब और पहल करने के बजाये भारत सरकार यह ध्यान रखेगी कि जो कदम वह उठाये वह रेसीप्रोकल हो अर्थात् पाकिस्तान भी उसके मुताबिक अपनी ओर से उसी प्रकार का कदम उठाये—अगर हम पाकिस्तान का एक जहाज वापिस करें, तो वह भी हमारा एक जहाज वापिस करे? अतएव मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार सबसे पहले ताशकन्द समझौते की सब शर्तें मनवाने के लिए पाकिस्तान सरकार पर जोर डालेगी?

आज पाकिस्तान से हमारे यहां रेफ्यूजीज आ रहे हैं।

**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य उसमें न जाये। यह डिस्कशन केवल रिजम्पशन आफ ट्रेड के बारे में है।

**श्री बेणी शंकर शर्मा :** हमारे यहां कहावत है : "भिरा गफूरा सवा सेर की लप्पी खा जायें, पर खा जाये किस भड्डू की?"

हम तो पाकिस्तान के साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिए तैयार हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भी इस बारे में कोई कदम उठाने के लिए तैयार है? वह अपने यहां से हिन्दुओं को भगा रहा है, जो रेफ्यूजी बनकर हमारे यहां आ रहे हैं और हम उसी से व्यापार की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान ताशकन्द समझौते की सब शर्तों का पालन नहीं करता है, तब तक उसके साथ व्यापार की चर्चा करना अपनी तौहीन कराना है।

हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान में इतना बड़ा प्रलयकारी तूफान आया। हमने इसके लिए पाकिस्तान की मदद करनी चाही। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें भी अमित्रतापूर्ण रुख अपनाया है। उसने हमारे हवाई जहाजों को अपने यहां नहीं जाने दिया और वहां भ्रमणशील अस्पतालों को भेजने की हमारी आफर को भी ठुकरा दिया।

इस अवस्था में क्या हम पाकिस्तान के साथ व्यापार भी इकतरफा ही करेंगे? व्यापार इकतरफा नहीं होता हम वहां से मछली लेना चाहते हैं; वह हमको नहीं मिलेगी। हां, हम अपना कायला वहां भेज सकते हैं लेकिन वह भी मुफ्त बिना मूल्य के। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जब तक पाकिस्तान ताशकन्द समझौते के मुताबिक अपने सब दायित्वों का पालन नहीं करता, तब तक भारत सरकार की ओर से इस बारे में कोई पहल नहीं की जायेगी?

**श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) :** सभापति महोदय, क्या भारत सरकार यूरोपियन कामन मार्केट की तरह हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक कामन मार्केट स्थापित कर के, जिसमें सीलोन और बर्मा भी सम्मिलित हों, दोनों देशों में व्यापार बढ़ाने का प्रयास करेगी? यदि दोनों देशों की

कामन मार्केट बनाना सम्भव न हो, तो जूट, मछली और कोयले जैसी खास खास कामोडिटीज का व्यापार करने के लिए, जिनकी दोनों देशों को जरूरत है, भारत सरकार पाकिस्तान के साथ कोई समझौता करने के लिए बातचीत करेगी ? क्या भारत सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत कर के दोनों देशों की सीमा पर होने वाले स्मगलिंग को खत्म करने का प्रयत्न करेगी ? यदि पाकिस्तान इन बातों को मानने के लिए तैयार न हो, तो क्या भारत सरकार इस मामले को कामनवैल्य की मीटिंग में उठायेगी, ताकि पाकिस्तान को समझाया जाये कि दोनों देश ट्रेड बेन को हटा दें ?

**श्री कंवरलाल गुप्त :** सम्भाषित महोदय, मैं इस बात से सहमत हूँ कि किसी भी पड़ोसी देश के साथ, चाहे वह पाकिस्तान हो या कोई और देश हो, हमारे अच्छे और मित्रता के सम्बन्ध होने चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों देशों का भला है। दोनों देशों में पूरा सहयोग भी होना चाहिए और व्यापार भी होना चाहिए। लेकिन इस बारे में एक तरफा कार्यवाही नहीं हो सकती है। पाकिस्तान के साथ हमारा सहयोग और व्यापार हो, मैं सिद्धान्त रूप में इस बात को मानता हूँ। लेकिन पिछले बीस साल में इस सरकार की स्पीजमेंट की पालिसी का क्या नतीजा निकला ? भारत सरकार ने कई बार पहल की है, लेकिन पाकिस्तान रिसपांड नहीं करता है। यह तो बन-साइडिड लव स्फेयर हो रहा है। भारत सरकार को ठोकरें पड़ती हैं, उसकी बेइज्जती होती है। जो पैक्ट होते हैं, पाकिस्तान द्वारा उनको तोड़ा जाता है।

अगर भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार करना है या अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने हैं, तो उसका सब से अच्छा तरीका यह है कि वह स्टेंग के साथ बात करे—वह यह स्पष्ट कर दे कि अगर पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करेगा, तो उसका उसी तरह से जवाब दिया जायेगा। तभी दोनों

देशों में को-आपरेशन, मेल और प्यार होगा। कायर के साथ कभी मेल नहीं होता है। क्या मंत्री महोदय इस बात का विश्वास दिलायेंगे कि पाकिस्तान ने हमारी जो करोड़ों रुपयों की प्रापर्टी जब्त कर रखी है, जिसको ताशकंद समझौते के मुताबिक हमें वापिस किया जाना चाहिए, जब तक वह उसको वापिस नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड की बात या पहल नहीं की जायेगी ? क्या सरकार यह आश्वासन देने के लिए तैयार है कि वह पाकिस्तान के संबंध में ऐसा कोई काम नहीं करेगी, जो इस देश के नेशनल इन्ट्रेस्ट्स के खिलाफ हो ?

अभी दोनों झा साहबान—झा स्ववेयर—ने कुछ बातें कहीं। इनके जो साथी मास्को में रहते हैं, जिन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट करवाया, जिनकी मदद से यह समझौता हुआ, हमारा तो कहना है कि वह दबाव में हुआ, तो उनको आप कहेंगे कि मेहरबानी करके यह जो इधर के लोग नहीं मानते हैं पाकिस्तान वाले जरा इनको समझाइए तो सही और अब तो अमेरिका की भी दोस्ती पाकिस्तान के साथ हो गई है तो अमेरिका को भी कहिए कि आप भी तो उनको समझाइए। हम दोस्ती जरूर चाहते हैं लेकिन बराबरी की हैसियत से।

**SHRI SWARAN SINGH:** Mr. Chairman, Sir, the queries and the doubts raised by one side—by one side, I mean, one way of thinking,—have been answered by my friends Shri Kanwar Lal Gupta and Shri Sharma and there is not much for me to say.

**AN HON. MEMBER:** You are in good company today.

**SHRI SWARAN SINGH:** I am always in good company. All Members of this House are very fine company so far as I am concerned.

The basic point in this is not theoretical. It is a question of what we have done and

[Shri Swaran Singh]

what more requires to be done. Before I answer the particular points raised, I would like to say it very clearly that we on our side have always held the view that there should be restoration of trade between India and Pakistan.

This was contained in the Tashkent Declaration also. We made several approaches to Pakistan, formal and informal approaches, suggesting that there should be restoration of trade. Then we took a decision on the 26th of May, 1966, when we unilaterally lifted the ban on trade with Pakistan with effect from the 27th of May, 1966. The Government of Pakistan was informed that we had lifted the ban on trade. It was the hope of the Government of India that the Government of Pakistan would respond; but they did not. This is the present factual position.

In view of this, what more is expected of us to be done, when a suggestion is made that we should take much more initiative?

One positive initiative we have taken is that we have removed restrictions on trade with Pakistan. Trade is a matter which cannot be settled by unilateral acts, because, we can remove the restrictions on trade, but the actual trade can take place only if the other side also cooperates; it is a matter which concerns the Government of that country. It may be the desire of the Chamber of Commerce and Industry, expressed through their Chairman, that it is in the interest of India and Pakistan that economic relations should be re-activated, that trade should be restored, that articles which are required by Pakistan, like coal and several other things can be more easily purchased at a lesser cost from India. This was the essence of the point made by Mr. Rahman who made the statement in his capacity as the Chairman of their Chamber of Commerce and Industry.

SHRI BHOGENDRA JHA: What is your reaction to it?

SHRI SWARAN SINGH: I have already indicated our reaction. I have said that we on our side are always ready and willing. And so, what more initiative we can take, is not quite clear to me. Even after hearing the suggestions made by Shri Bho-

gendra Jha, I do not know what more initiative we can take. Unless the other side is responsive, merely our making statements will not be regarded as initiative. Towards the end of his comments, he did say that the situation might change after the election that is going to take place in Pakistan. Whether election takes place or does not take place, whatever may be the internal set-up, it is only their concern. Irrespective of the political set-up and the form of it, which is only their concern, we on our side are prepared to reactivate our economic relations in the form of trade and in several other economic fields. We have adopted this attitude because we genuinely feel that the people on both sides stand to gain by reactivation of trade.

Hon. Members have mentioned some commodities. But there are several others also, and the list can be increased to the mutual benefit of both countries. This has been our grievance that notwithstanding the obvious advantage of trade between the two countries, the administration and the Government in Pakistan have turned a blind eye to the obvious economic benefits that are bound to arise if trade is restored. They have adopted a negative attitude and have tried to link the reactivation of economic ties with other political issues, and their line generally has been that unless they receive satisfaction on certain other issues which are political in their essence, namely the Kashmir issue or the Farakka issue, they do not want to take any step which might result in general relaxation of tension and improvement of relations. This, unfortunately, has been the attitude of the Government of Pakistan. In the face of this, my attitude is not to put counter-arguments or to suggest anything in a sort of mood of explaining away our attitude. We ourselves are quite clear and I would like to reiterate our policy in unmistakable terms that we would welcome the restoration of trade. We would welcome the reactivation of economic ties. If we have not succeeded so far, I would like to say that it is not because we have been either hesitant or obstructionist but because all this obstruction and hesitation has come from the other side. Whether this will disappear after the elections is a matter on which I cannot speculate. Only time will show whether the economic forces which are compelling have

really come on the top and have quietened their rather negative attitude in this matter of trade.

**SHRI BHOGENDRA JHA:** Is he going to make any attempt or any move in combination with the Governments of Iran and Afghanistan in regard to the land route?

**SHRI SWARAN SINGH:** Regarding this question, we have always shown interest in using the land route for trade with Afghanistan and Iran, but in between is the area of Pakistan, and unless they agree, we cannot make much progress.

For the information of the House, I would like to say that Pakistan has allowed movement of certain commodities from Afghanistan, but it is a one-way traffic in the sense that certain articles such as fresh fruit and certain other articles are permitted to be moved over the Pakistan territory from Afghanistan into India, but nothing is allowed to be moved from India across Pakistan into Afghanistan. That is the present position. We are interested in developing this trade across the land routes also. But, unfortunately, at the present moment, Pakistan is adopting a negative attitude. We hope that in course of time, these countries, namely Iran and Afghanistan will also see the wisdom of utilising this land route for the purpose of movement of goods on either side. We would greatly welcome any such development. We are also prepared to work for it. But it is no use my making unilateral moves one after the other without having a positive response from the other side. We are in touch with the Government of Pakistan. We have remained in touch with them. At the present moment, I do not see much opening. It will be wrong for me to create a feeling that things are going to move in this direction. If a new government comes into existence after the elections or if the present regime continues in its present form or in any other form, then only after some time one can say whether one is likely to succeed in this respect or not.

Having given this information, I would very briefly like to answer now some of the specific points that have been raised.

Shri Bhogendra Jha said that it is under the pressure of USA or other capitalist

countries that we are showing lack of interest in reactivating the trade route across Pakistan in the matter of trade between India on the one side and Iran and Afghanistan on the other. I would very categorically state that there has been no such pressure, direct or indirect, from the USA, either officially or unofficially, from which one can justify a remark of that type. I would very strongly say there is no substance in this feeling. If any such feeling exists anywhere, I would categorically reject it because it does not exist factually.

We are anxious that the economic relations should revert to the pre-1965 position. It was with that view that we unilaterally removed restrictions on trade. On principle, I agree; whether fish will be the commodity or it will be jute—there are several other articles which can usefully form the subject matter of this trade—can be decided upon, but all this is wishful thinking unless the Pakistan Government is prepared to make any move.

Both Shri Sharma and Shri Kanwar Lal Gupta expressed their view in almost identical terms. The only question Shri Sharma put was whether we should not say that we would not resume trade unless all the conditions in the Tashkent Declaration were observed. Our general approach has been that step by step we are prepared to unravel and untie whatever may be the knots, and we do not want to tie one with the other; we should try to improve relations without presenting a packet which may not take shape and ultimately nothing may happen. That is not our attitude.

**SHRI S. C. Jha** asked whether there was any possibility of a common market. First, there should be the possibility of a market at any rate before we can think of a common market. At the present moment, I do not see even a market. So it will be too early for me to hold out any hope of a common market. Once these economic relations are restored and trade reflows, then a common market is only a strategy which will control the movement and the fiscal aspects of trade; otherwise, I do not see any chance of jumping over the trade and thinking about a common market.

Border smuggling: yes, it should be stopped and we are taking every step to stop it. He

[Shri Swaran Singh]

suggested we should raise it at the Commonwealth Prime Ministers' conference. We have no intention to do so because all these bilateral issues should be raised and settled between the two countries without trying to internationalise them.

Shri Kanwar Lal Gupta put three questions. He said I should talk with strength. Of course, I have my own way of putting across these view points. But I would like to assure the House that national interest is always uppermost in our mind and no fresh assurance on that score is necessary. We will try to pursue a policy which is to the mutual interest benefit of the people of India and Pakistan, because I believe that

whatever may be the attitude of the Pakistan leaders, the people of both States, India and Pakistan, want to live as good neighbours and in peace and all these other tensions that are created are created by certain groups who want to perpetuate their own hold, stranglehold. We have to proceed cautiously, but we have to respond to every step. In fact, we should take even the initiative to reduce tension and improve relations.

18.00 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Monday, December 7, 1970/Agrahayana 16, 1892 (Saka).*